भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग से संबंधित दिसंबर, 2021 माह का मासिक सार।

न्याय विभाग से संबंधित दिसंबर, 2021 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

1. **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 में संशोधन।**

   उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 में संशोधन को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। यह संशोधन अधिनियम दिनांक 20-12-2021 को अधिसूचित किया गया था।

2. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)**

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में, विधिक सेवा प्राधिकरणों ने पूरे देश में 11 दिसंबर, 2021 को 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कीं जिनमें 6,938 करोड रुपए समझौता मूल्य के 46.95 लाख मामलों का निपटारा किया गया।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में, उत्तराखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 5-12-2021 को पिथौरागढ़ में एक विशाल कानूनी सहायता कैंप आयोजित किया गया था। माननीय विधि और न्याय मंत्री, श्री किरण रिजीजू और भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित इस समारोह में उपस्थित हुए। इस विशाल कानूनी सहायता कैंप में, कुटा, चौरानी, मदनपुरी, जमादारी और भागीचौरा ग्रामों के गांव वासियों को शामिल किया गया था। इन ग्रामीणों को कानूनी सहायता देने के अलावा निशुल्क दवाइयां, कंबल, शॉल, वस्त्र और रोजमर्रा की जरूरतों की सामग्रियां भी वितरित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए

दिव्यांग व्यक्तियों को 50 व्हीलचेयरों, 50 वैशाखियों, 600 चश्मों, 500 ईयर मशीनों, मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ ने मदनपुरी, जामतारी, कुटाचौरानी, किमखौला, भक्तिरावन, गनागांव, औलताड़ी, कुललेख और चिफलतारा नामक 9 गांवों को उनमें रहने वाले ग्राम वासियों के पुनर्वास के लिए गोद लिया।

3. ईकोर्ट मिशन मोड परियोजना-II

- 30 नवंबर, 2021 तक 447 ई सेवा केंद्रों को 22 जिला न्यायालयों में कार्यात्मक बनाया गया है। इन ई सेवा केंद्रों को ईकोर्ट परियोजना और राज्य निधि दोनों से निधि उपलब्ध कराई गई है।
- ई सेवा केंद्रों और अन्य नई परियोजनाओं को चालू किया गया: उच्चतम न्यायालय की ई समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 2 माह के दौरान कुछ नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने हाल ही में निम्नलिखित का उद्घाटन किया है;
    - क) ई फाइलिंग में मदद करने के लिए और इसकी सुविधा के लिए उच्च न्यायालय और 6 जिला न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग स्टेशन;
    - ख) अभिलेखों के परिरक्षण, डिजिटलीकरण,पुरालेख और पुनर्प्राप्ति आदि सभी को एक ही स्थान पर लाने के लिए उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड रूम डिजिटलीकरण केंद्र; और
    - ग) उड़ीसा के माननीय मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य माननीय न्यायाधीश के न्यायालय में पहला कागज रहित न्यायालय;
    - घ) वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर के साथ हाइब्रिड ऑडियो और वीडियो टेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार किया गया एक वर्चुअल कोर्ट रूम मलकानगिरी जिला न्यायालय में चालू किया गया था;
    - ड़) ई कस्टडी प्रमाण पत्र प्रणाली के साथ-साथ वर्चुअल कोर्ट रूम अंगुल और नयागढ़ जिला न्यायालय परिसरों में चालू किए गए।
- इसी प्रकार से , ई सेवा केंद्र और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन का त्रिपुरा के 3 न्यायिक जिलों में हाल ही में उद्घाटन किया गया है।
- उत्तराखंड राज्य में पहला ई सेवा केंद्र उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चालू किया गया।
- सिक्किम में सात ई सेवा केंद्रों और दिल्ली, इलाहाबाद में एक एक ई सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया गया।

- लाइव स्ट्रीमिंग: झारखंड और पटना उच्च न्यायालय नामक दो और उच्च न्यायालयों ने न्यायालय की कार्यवाहियों में लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ कर दी है।
- वर्चुअल कोर्टः हिमाचल प्रदेश में एक और वर्चुअल कोर्ट खोला गया जिससे अब 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 17 वर्चुअल कोर्ट हो गए हैं। इन वर्चुअल कोर्ट द्वारा 1.07 करोड़ से अधिक मामलों को देखा गया है और पहली बार 200 करोड़ रुपए के ऑनलाइन जुर्माना संग्रह की सीमा को पार किया गया।
- भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने मई, 2020 से नवंबर, 2021 तक,ईकोर्ट परियोजना के तहत दी गई आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 3,02,614 व्यक्तियों को शामिल किया गया जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला स्तर के न्यायाधीश,, न्यायालय स्टाफ, मास्टर ट्रेनर और अधिवक्ता आदि शामिल थे।
- गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा *ईमेल माई केस स्टेटस* सेवाः कोविड-19 वैश्विक महामारी और अधिवक्ताओं एवं वादियों के व्यक्तिगत रूप से पहुंचने से जुड़ी चुनौतियों के परिपेक्ष में, गुजरात उच्च न्यायालय एक ऐसी सुविधा विकसित कर रहा है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने अनुरोध के आवश्यक ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अपने विकल्प के ईमेल पते पर उच्च न्यायालय के मामलों की स्थिति और उस विशिष्ट मामले में आगे की सभी अद्यतन जानकारी स्वयं ही प्राप्त कर सकेगा। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा विकसित की जा रही इस *ईमेल माई केस स्टेटस* सेवा वर्चुअल केस स्टेटस इंक्वायरी काउंटर अथवा केस स्टेटस ई काउंटर के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करेगी साथ ही इसमें सभी या कोई भी व्यक्ति अपने वांछित मामलों की आगे की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने की भी सुविधा जोड़ी गई है।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एन एस टी ई पी- कोविड-19 प्रारंभ होने के समय से,जिला न्यायालय ने 1,08,36,087 मामलों की सुनवाई की जबकि उच्च न्यायालय ने 57,39,966 मामलों की सुनवाई की और इस प्रकार से दिनांक 30.11.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके 1.65 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। समन देने और समन जारी करने की प्रक्रिया के लिए नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस 26 राज्यों में शुरू की गई है।

4. टेली लॉ

- 30,680 व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई। 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 12,81,591 मामलों में कानूनी सलाह दी गई।
- 3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए जिनमें राज्य स्तर के 139 समन्वयकों/जिला प्रबंधकों/ग्राम स्तर के उद्यमियों/पैरा लीगल स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

5. विधिक साक्षरता प्रोग्राम

- सिक्किम राज्य महिला आयोग ने 210 कॉलेज छात्रों और 34 शिक्षकों के लिए घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बाल यौन शोषण से संबंधित कानूनों पर बर्टुक, ईस्ट सिक्किम में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
- अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के 51 गांव वृद्धों और गांव वृद्धाओं के लिए दस्तूरी प्रथाओं और औपचारिक कानूनों के बीच तालमेल पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर ने 69 चिकित्सकों और चिकित्सा व्यवसाइयों के लिए यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

6. न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विस)

- इस माह के दौरान 107 नए वकीलों ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल पर पंजीकरण किया है। न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन के तहत कुल 3710 वकील (3254 पुरुष, 454 महिला, 02 ट्रांसजेंडर) पंजीकृत हो चुके हैं।
- न्याय बंधु पैनल के तहत अब तक14 उच्च न्यायालयों द्वारा 502 प्रो बोनो वकीलों का नामांकन किया गया है।

7. न्यायपालिका और फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्टों हेतु बुनियादी ढांचा विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम:

विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने न्यायिक बुनियादी ढांचे की समीक्षा के विषय पर दिनांक 20-12-2021 को एक बैठक आयोजित की।

***